

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2023 — वैशाख 8, शक 1945

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-26 / 2019 / रो.वि. / 42.— जहां कहीं आधार का उपयोग एक परिचय पत्र अभिलेख के रूप में सेवाओं के वितरण प्रक्रिया या फायदे या अनुवृत्ति के लिए किया जाता है जो सरकार की वितरण प्रक्रिया को सरलीकृत करती है, पारदर्शिता और क्षमता को प्रदर्शित करती है और हितग्राहियों को उनकी पात्रता को प्रत्यक्ष रूप से आसान एवं सुविधापूर्वक निर्बाध रूप से प्रदान करने में परिचय पत्र के लिए सबूतों के रूप में लिये जाने वाले विविध अभिलेखों से छुटकारा दिलाता है।

और जहां, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रोजगार इच्छुक आवेदकों का पंजीयन एवं बेरोजगारी भत्ता योजना का संचालन करना है, जिसमें ऐसे रोजगार इच्छुक आवेदकों को जो रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें स्वयं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार और विकसित किये गये पोर्टल में पंजीकृत करना है।

और जहां, योजना के अंतर्गत, रोजगार इच्छुक आवेदकों को अद्यतन रोजगार सहायता प्रदान की जाती है जो पोर्टल में स्वयं को क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप पंजीकृत करते हैं।

और जहां उक्त योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन में समेकित निधि आवर्ती से व्यय होता है।

अतः इसलिए आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ) एवं सेवा का अधिनियम, 2016 की धारा-7 का उपयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन इस प्रकार निम्नानुसार अधिसूचित करता है। अर्थात्: —

- (1) कोई भी निवासी व्यक्ति जो उक्त योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे आधार क्रमांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा।
(2) कोई भी निवासी व्यक्ति जो योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है और जिसके पास आधार क्रमांक नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है को अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति पर आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। (बाल लाभार्थियों का मामले में) बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे बच्चे किसी भी आधार नामांकन केंद्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर जाकर आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के नियम-12 के अनुसार, विभाग को अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन हितग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हुए हैं और आधार नहीं होने की स्थिति में संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में रिस्त नामांकन केंद्र, नहीं होने पर विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

बशर्ते कि जब तक व्यक्ति को आधार नहीं दिया जाता है, तब तक योजना के तहत लाभ ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर दिया जाएगा, अर्थात्: –

(अ) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ब) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्: –

- (i) बैंक या पोर्ट ऑफिस का फोटो युक्त पासबुक; या
- (ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
- (iii) पासपोर्ट; या
- (iv) राशन कार्ड; या
- (v) मतदाता पहचान पत्र; या
- (vi) मनरेगा कार्ड; या
- (vii) किसान फोटो पासबुक; या
- (viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या
- (ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो युक्त पहचान का प्रमाण पत्र; या
- (x) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़;

बशर्ते कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नामित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजनान्तर्गत हितग्राहियों को सुविधापूर्वक लाभ उपलब्ध कराने हेतु विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितग्राहियों को योजनान्तर्गत आधार की आवश्यकता से अवगत कराने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात् –

(अ) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस प्रमाणीकरण की सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से आईरिस स्कैनर या फेस प्रमाणीकरण के साथ-साथ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रूप से लाभ दिया जा सके।

(ब) उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव हो, आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणीकरण स्वीकार्य होगा।

(स) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के तहत भौतिक आधार पत्र के आधार पर लाभ दिया जा सकता है, जिसका प्रमाणीकरण आधार पत्र पर मुद्रित विक रिसपोन्स कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है। विक रिसपोन्स कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत कोई भी वास्तविक लाभार्थी (बच्चों के अतिरिक्त) मिलने वाले लाभों से वंचित न हो, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभाग के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेंगे जैसा कि लायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक D-26011/04/2017-डीबीटी, दिनांक 19 दिसंबर 2017 में निर्दिष्ट है। (<https://dbtibharat.gov.in/> पर उपलब्ध)

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

Atal Nagar, the 24th April 2023

NOTIFICATION

No. F-5-26/2019/R.V./42.— Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Skill Development, Technical Education and Employment Department, Government of Chhattisgarh, is administering the Registration of Job Seekers and Berojgari Bhatta Yojna to job seekers who want to get job assistant through employment exchange wherein they have to register themselves in the portal, which is being designed and developed by the National Informatics Centre, Chhattisgarh State Centre, Mantralaya, Nava Raipur Atal Nagar, Chhattisgarh;

And whereas, under the Scheme, updated job assistance is given to the job seekers who get registered themselves in the portal, by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Chhattisgarh State;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Chhattisgarh hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual who desires to avail the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries), provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals subject to production of the following documents, namely:-

- (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
- (b) any one of the following documents, namely :-
 - (i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
 - (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
 - (iii) Passport; or
 - (iv) Ration Card; or
 - (v) Voter Identity Card; or
 - (vi) MGNREGA card; or
 - (vii) Kisan Photo passbook; or
 - (viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
 - (x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

- (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
- (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
- (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bona fide beneficiary (other than children) under the Scheme is deprived of his due benefits, the concerned Department in the State Governments and Union Territory Administrations shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on <https://dbtbharat.gov.in/>).

5. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.